

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,  
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

निबन्धक,  
लोक सेवा अधिकरण,  
316 फेज-II  
बसन्त बिहार, देहरादून ।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक १ अगस्त, 2008

विषय-लोक सेवा अधिकरण उत्तराखण्ड देहरादून में पदों का सृजन किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या- 326 / न्याय विभाग / 2001 दिनांक 4 जुलाई, 2001 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2- श्री राज्यपाल, उक्त शासनादेश द्वारा सृजित सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के वेतनमान रु० 6500-10500 में सृजित 02 पदों को तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुये जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) को देय फीस दरों के समरूप फीस दरों पर प्रस्तुतकर्ता अधिकारी पदनाम से 02 पद (एक देहरादून व एक नैनीताल के लिये) सृजित करते हुये इन पर विधि व्यवसायियों को चयन समिति के माध्यम से आवद्ध किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

3- जब तक चयन समिति के माध्यम से प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को आवद्ध किया जायें तब तक पूर्व तदर्थ रूप से कार्यरत सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों से प्रस्तर -7 में उल्लिखित फीस दरों पर अधिकरण में शासन की ओर से मुकदमों की पैरवी का कार्य लिया जायेगा ।

4- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के आबन्धन हेतु विधि व्यवसायी के लिये यह आवश्यक है कि वह कम से कम 10 वर्ष की वकालत का अनुभव रखता हो तथा उसे सेवा विधि शास्त्र की समुचित जानकारी हो ।

5- यह आवद्धता पूर्व में 01 वर्ष के लिये हो सकती है जिसे सम्बन्धित विधि व्यवसायी की योग्यता एवं आवश्यकता के दृष्टिगत बढ़ाया जा सकता है :

परन्तु, विधि व्यवसायी के 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, उसके कार्यकाल का नवीनीकरण नहीं होगा ।

6- प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों का चयन न्याय विभाग द्वारा सम्पादित कराया जायेगा इस समिति में निम्नांकित सदस्य होंगे :-

- (1) प्रमुख सचिव/सचिव कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन
- (2) अध्यक्ष, उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण
- (3) प्रमुख सचिव/सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी उत्तराखण्ड शासन

7- लोक सेवा अधिकरण में आबद्ध प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों का स्तर जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) के समान होगा। जिन्हें सरकारी कर्मचारियों का दर्जा प्राप्त नहीं होगा बल्कि सरकार का उनसे सम्बन्ध मुवक्किल-वकील (क्लाइन्ट-काउन्सिल) का होगा। यह एक सिविल पद नहीं है अपितु व्यावसायिक आबद्धता है जिसे कभी भी राज्य सरकार अथवा आबद्ध अधिवक्ता द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना एवं प्रतिकर के कभी भी समाप्त किया जा सकता है। आबद्ध प्रस्तुतकर्ता अधिकारी शासन के विरुद्ध लोक सेवा अधिकरण, मा0 उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय में सेवा सम्बन्धी किसी वाद की पैरवी/बहस नहीं करेंगे। जिन मामलों में उन्हें शासन द्वारा विशेष अधिवक्ता नियुक्त किया जायें उनमें भी वह शासन की ओर से पैरवी करेंगे।

8- आबद्ध किये गये प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों को कृत कार्य के आधार पर जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) के समान वर्तमान में नियत निम्नलिखित रिटेनर फीस/पारिश्रमिक देय होगा जिसका भुगतान उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण द्वारा नियमानुसार किया जायेगा :-

- |     |   |                        |
|-----|---|------------------------|
| (1) | रिटेनर फीस  | -रु0 1875.00 प्रति माह |
| (2) | वाद/अपील/मेमो/प्रार्थना पत्र पुनरीक्षण<br>प्रार्थना पत्र (रिवीजन) | -रु0 300.00 प्रति केस  |
| (3) | लिखित विवरण/पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र                              | -रु0 150.00 प्रतिकेस   |
| (4) | वादों एवं प्रकीर्ण वादों में बहस के लिये                          | -रु0 465.00 प्रतिदिन   |

उपरोक्त रिटेनर फीस/पारिश्रमिक के अतिरिक्त कोई मंहगाई भत्ता, अतिरिक्त मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता तथा अन्य कोई भत्ते/सुविधा देय नहीं होंगे परन्तु वाद सम्बन्धी कार्य के निष्पादन हेतु स्टेशनरी आदि की व्यवस्था भी लोक सेवा अधिकरण द्वारा भी की जायेगी।

9- प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों को रिटेनर फीस एवं अन्य पारिश्रमिक के रूप में देय धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष के आय व्ययक की अनुदान संख्या 04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-800 अन्य व्यय-04-लोक सेवा अधिकरण-00-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान" के नामें डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 240 एन0पी0/XXVII/08 दिनांक 31 जुलाई, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

( आर0डी0पालीवाल )

सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी

संख्या- 232(1) / XXXvi(1)/2008-850/2001 तददिनांक ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर बिल्डिंग माजरा, देहरादून ।
- 2- प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
- 3- उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, नैनीताल पीठ, जिला न्यायालय परिसर नैनीताल ।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/नैनीताल ।
- 5- सम्बन्धित सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा- उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, देहरादून ।
- 6- वित्त अनुभाग-5/एन0आई0सी0/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

( आलोक कुमार वर्मा )

अपर सचिव,